



## प्रधानमंत्री आवास योजनाएं ( शहरी )

आवास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) / कम आय वर्ग(LIG) तथा मध्यम आय वर्ग (MIG) के लिए आवास निर्माण / क्रय हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज अनुदान की योजनाएं जारी की गई हैं, जिन्हें बैंक द्वारा लागू किया गया है। योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है -

(अ) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) / कम आय वर्ग(LIG)के लिए आवास निर्माण / क्रय हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज अनुदान की योजना - योजना के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं -

(1) योजना का नाम - CLSS for EWS / LIG

(2) योजना अवधि - वर्ष 2015 से 2022 तक

(3) हितग्राही - ऐसे परिवार जिनके किसी भी सदस्य के नाम भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं हैं। परिवार के अंतर्गत पति, पत्नी एवं अविवाहित पुत्र / पुत्री को माना जाएगा। परिवार की महिला प्रमुख को प्राथमिकता दी जाएगी अथवा महिला के साथ पुरुष (पति / पत्नी) को संयुक्त रूप से ऋण सुविधा दी जाएगी।

(4) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) - ऐसे हितग्राही जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रु.3,00,000.00 लाख तक है, वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आएंगे। इस वर्ग के आवास का कुल कारपेट एरिया मूलभूत सुविधाओं सहित 30 वर्ग मीटर तक होगा।

(5) कम आय वर्ग (LIG) - ऐसे हितग्राही जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रु.3,00,001.00 से रु. 6,00,00.00 लाख तक है, वह कम आय वर्ग की श्रेणी में आएंगे। इस वर्ग के आवास का कुल कारपेट एरिया मूलभूत सुविधाओं सहित 60 वर्ग मीटर तक होगा।

(6) अनुदान हेतु पात्र ऋण राशि - योजनान्तर्गत रु. 6.00 लाख तक के ऋण पर ब्याज अनुदान प्राप्त होगा।

(7) ब्याज अनुदान - योजनान्तर्गत 6.5% की दर से अधिकतम 20 वर्ष तक अथवा ऋण की निर्धारित अवधि, जो भी पहले हो, तक ब्याज अनुदान की पात्रता होगी। योजना के अन्य घटकों के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले हितग्राही उक्त ब्याज अनुदान हेतु पात्र नहीं होंगे।

(8) अन्य - हितग्राही को योजना में दिए गए निर्देशों के अनुरूप आवास निर्माण / क्रय एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे।

(9) कवरेज - वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सभी वैध कस्बा (Town) और CLSS for EWS / LIG के लिए नोटिफाइड कस्बे भी पात्र होंगे।

(10) योजनान्तर्गत आवास ऋण के आवेदन सीधे बैंक को प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

(2)

(ब) मध्यम आय वर्ग (MIG) के लिए आवास निर्माण / क्रय हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज अनुदान की योजना - योजना के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं -

(1) योजना का नाम - Credit linked Subsidy Scheme For Middle Income Group

(2) योजना प्रारंभ दिनांक - 01/01/2017

(3) पात्रता - (i) ऐसे परिवार जिनके किसी भी सदस्य के नाम भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं है।

(ii) परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित पुत्र / पुत्री माने जाएंगे। परिवार के ऐसे वयस्क व्यक्ति, जिसकी स्वतंत्र आय है तो परिवार से अलग माना जा सकता है। विवाहित पति/पत्नी में से किसी एक को ब्याज अनुदान की पात्रता आय सीमा के अधीन होने पर होगी।

(iii) हितग्राही या उसके परिवार द्वारा भारत सरकार की किसी आवास योजना का लाभ न लिया गया हो।

(4) मध्यम आय वर्ग की श्रेणी -

(i) MIG-I - प्रतिवर्ष रु.6,00,001/- से रु. 12,00,000/- तक की आय वाले इस श्रेणी में आएंगे।

(ii) MIG-II - प्रतिवर्ष रु. 12,00,001/- से रु. 18,00,000/- तक की आय वाले इस श्रेणी में आएंगे।

(6) कार्पेट एरिया - (i) MIG-I के लिए 90 वर्ग मीटर एवं MIG-II के लिए 110 वर्ग मीटर कुल कार्पेट एरिया मूलभूत सुविधाओं सहित निर्धारित।

(7) ब्याज अनुदान हेतु पात्र ऋण राशि - MIG-I हेतु रु.9,00,000/- एवं MIG-II हेतु रु. 12,00,000/-

(8) ब्याज अनुदान - MIG-I के हितग्राहियों को 4% एवं MIG-II के हितग्राहियों को 3% ब्याज अनुदान 20 वर्ष तक अथवा ऋण की निर्धारित अवधि, जो भी पहले हो, तक ब्याज अनुदान की पात्रता होगी

(9) कवरेज - वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सभी वैध कस्बा (Town) और CLSS-MIG के लिए नोटिफाइड कस्बे भी पात्र होंगे।

(10) अन्य - हितग्राही को योजना में दिए गए निर्देशों के अनुरूप आवास निर्माण / क्रय एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे।

(11) योजनान्तर्गत आवास ऋण के आवेदन सीधे बैंक को प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

योजनाओं की विस्तृत जानकारी हेतु नजदीकी शाखा से संपर्क करें।